के बारे में हमारे ऑनरेबल साथी जॉन फर्नांडिस साहब ने अपनी बात रखी है। सच यह है कि प्राइम लैंड जो काश्त में इस्तेमाल होती है, हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग की सारी जो लैंड डैवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, पी०डब्ल्यू०डी० है, इरीगेशन है, स्टेट्स के कई ऐसे महकमे हैं जो नहर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, लिंक रोड बनाने के लिए, और पंचायतघर बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए काश्तकारों से काफी जमीन—हजारों-हजार एकड़ जमीन लैंड ऐक्वीज़िशन ऐक्ट के अन्तर्गत, जो अमैंड हुआ है, 1984 में अमैंड भी हुआ और जब कि उसके अंदर यह प्रोवीजन कर दिया गया कि मार्किट रेट दिया जाएगा। यह भी प्रोवीजन कर दिया कि जिस रोज से दिया जाएगा, अगर उसे कम्पनसेशन अदा नहीं हुआ है तो उसका इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। लेकिन यह होता नहीं है होता यह है कि कोई भी ऐजेंसी जो मकान बना रही है, इंदिरा आवास बना रही है गांव की सभाओं की जमीन ले ली जाती है। जो हाउसिंग बोर्ड स्कीम्स चलती है, बड़ी-बड़ी डैवलपमेंट अथारिटीज़ की चलती है—हमारे उत्तर प्रदेश के 85 जिले हैं, कम से कम 30—40 ऐसी डैवलपमेंट अथारिटीज़ बन गयी हैं, मुरादाबाद बन गयी है, बरेली बन गयी है, गोरखपुर बन गयी है, बहुत सी डैवलपमेंट अथारिटीज बन गयी हैं, यह जमीनें लेती हैं, प्राइम लैंड लेती हैं—काश्तकारों की और जो किनारे—किनारे की जमीन है, जो शहर के किनारे की खेतिहर जमीने हैं, जिस पर सब्जियां बोई जाती हैं, उन जमीनों को ले लेती हैं। न सिर्फ ले लेते हैं बल्कि उसका कम्पनसेशन भी नहीं देते हैं.....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप सिर्फ एसोसिएट करिएगा। आप इतना लम्बा स्टेटमेंट मत करिए। अभी तो एक स्टेटमेंट और आना है।

श्री खान गुफरान जाहिदी: जब मैंने देखा कि सभी बोल रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कहूं। मैं आपको इन्फारमेशन दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। मेरा कहना यह है कि किसानों की जमीन ले ली जाती है और उसका इस्तेमाल तीन साल तक नहीं होता है। यह सच बात है। अगर तीन साल तक कोई अथारिटी काम नहीं करती है और वह किसानों से जमीन लेकर डाल देती है। उस जमीन पर किसान अपनी खेती भी नहीं कर सकता है इसलिए उसका जब तक सही तौर पर प्लान तैयार न हो जाए उस वक्त तक उस पर खेती करने की इजाजत किसान को दी जानी चाहिए। उस वक्त तक कोई काम न किए जाए जब तक कि उसका पैसा, कम्पनसेशन अदा न कर दिया जाए। ऐसा भी हुआ है कि मकान बन गए और मकान बनने के बाद जब मकानों का अलाटमेंट शुरू हुआ तो किसान बड़ी तादाद में आकर खड़े हो गए और उन्होंने मकानों का अलाट नहीं होने दिया और उनका हंगामा काफी दूर तक बढ़ता चला गया .....(**व्यवधान**).....

श्री सतीश प्रधान: मैडम, जब हम बात कर रहे थे तो हमें ....(**व्यवधान**).....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मैं अगर आपको अलाऊ नहीं करती प्रधान जी तो शायद इनको भी अलाऊ नहीं करना पड़ता। लेकिन आपको मैंने देखा कि You are an experienced person, I allowed you. Now he also wants to contyribute something.

श्री खान गुफरान जाहिदी: मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत से सूबों ने अपने-अपने यहां भी लैंड एक्वीजिशन एक्ट बनाए हैं लेकिन सेन्ट्रल एक्ट उन पर हावी है। बहुत जगह पर जिन्होंने सदर हिन्दुस्तान से अपनी मुहर लगा ली है, वह अपना लैंड एक्वीजिशन एक्ट खुद चला रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से कहना इतना सा है कि उस वक्त तक कोई काम न किया जाए काश्तकारों की जमीन का जब तक कि उनको कम्पनसेशन मय इन्टेरस्ट के न दे दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): थैंक्यू बहुत-बहुत धन्यवाद।

STATEMENT BY MINISTER

National Social Assistance Programme

The Minister of State of the Ministry of Rural Development (Shri Babagounda Patil): Madam, the National Social Assistance Programme (NSAP) is being implemented since 15th August, 1995. It has three components at present. Under National Old Age Pension Scheme (NOAPS), the Central assistance is given @ Rs. 75/- per month to destitutes who are aged 65 years or more. Under National Family Benefit Scheme (NFBS), lumpsum benefit is given to households below poverty line on the death of the primary breadwinner. An amount of Rs. 5,000/- is given in case of natural death and Rs. 10,000/- in case of accidental

death. Under National Maternity Benefit Scheme (NMBS), pregnant women belonging to households below poverty line are given assistance of Rs. 300/- upto two live births.

On the 7th July, 1998, the Government has decided to amend the National Social Assistance Programme (NSAP) Guidelines to make the programme more effective. The benefit under National Family Benefit Scheme (NFBS) has been raised to Rs. 10,000/- from Rs. 5,000/- in case of natural death of primary breadwinner. Taking note of the fact that poor households have more than one breadwinner in order to survive, under National Family Benefit Scheme (NFBS), primary breadwinner (man or woman) shall henceforth be defined as member whose earnings had contributed substantially to the household income. the term "household" shall also include minor brothers/sisters in case of death of an unmarried adult. The benefit under National Maternity Benefit Scheme (NMBS) has been raised to Rs. 500/- from Rs. 300/-. while timely disbursement of benefit under National Maternity Benefit Scheme (NMBS), before the child is born will be ensured, this benefit will not be denied if there is delay in applying and the benefit can be paid even after delivery of the child. The assistance under three schemes will now be sanctioned and disbursed in the meetings of Gram Sabha by Gram Panchayats/ Block level functionaries. In case of Urban areas. elected local self-government officials are to be involved in the process of sanctioning and disbursement of assistance. The disbursement will be made in public meetings of mohalla/neighbourhood committees.

SHRI SANATAN BISI (ORISSA): Madam, I thank you for giving me this opportunity. Madam, as far as the National Social Assistance Programme is concerned, there was an Unstarred Question No. 843 on 3rd June, 1998. As per this statement, the amount was released for the years 1995-96, 1996-97 and 1997-98. Madam, you will be surprised to know when I visited Kalahandi, Bolangir and Sambhalpur KBS Districts are different, drought-prone area is different, starvation pocket is different—I made an inquiry from the concerned officers and people and I was told that they have not received any amount. Though they had received several applications, they were not able to pay them for want to funds for this purpose. I would like to know categorically from the Minister, as for Orissa is concerned, when the amount under the National Social Assistance Programme was released. When I made a field inquiry in Kalahandi, Bolangir and Sambhalpur, I got, information from the Collector that there was no fund with them for this purpose and so they could not give any amount to the beneficiaries. I would like to know on which date the amount for 1997-98 was released to the State of Orissa. Since these are poverty-stricken places, I would like to know the number of beneficiaries. I also request that the target of beneficiaries should also be increased. These are my submissions. Thank you.

SHRI JOHN F. FERNANDES (GOA): Madam, I have to compliment the Minister because he is going to help the poorest of the poor in this country. Our congratulations will be in place provided this scheme is properly implemented and the beneficiaries receive this amount. I do not think just involving the elected representatives and doling out this amount at some functions will suffice. I would like to know whether the Government has thought of any mechanism to see that this amount reaches the deserving people. I feel that this amount should be given to only those people who have proper identity cards. Otherwise, I do not think just by involving bureaucrats and the elected representatives, this amount will reach them. So, the Government should have a proper mechanism and this amount should be distributed by cheques or through post-offices. As rightly mentioned by my collegue, any scheme involving cash incentives cannot be suc-

cessful in this country, not because the bureaucracy is dishonest but because it will not just reach there. We know that there are many schemes in this country. I suggest that instead of giving cash incentives, they should give foodgrains to the people who are living below the poverty line. What is the machinery involved to see that it is implemented in the States properly? I would like to know whether the machinery of the State Governments and that of the Central Government would be coordinating with each other. We have seen that the funds given for a specific purpose have been diverted elsewhere. I do not want to name these States. I would like to know the mechanism evolved by the Government for this purpose and the total amount released so far. It should not be like MPs Fund where in no funds are coming to the Collectors from the Government. I would like to know whether this amount has already been reimbursed to the States for this purpose. Thank you, Madam.

श्री खान गुफरान जाहिदी (उत्तर प्रदेश): मैडम, मैं मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने कुछ पैसे बढ़ाए हैं। लेकिन मेरे नोडल डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर में बिलो पावर्टी लाइन के तहत गरीब लोगों के मरने पर जो पैसे दिये जाते हैं, उसके हमारे यहां 4-5 केसेज चल रहे हैं। पंचायत के सैक्रेटरी और प्रधान जी ने मिलकर एक गांव के 25-30 आदमियों को मार दिया और उनके पैसे निकाल लिये। अब सैक्रेटरी और प्रधान जी सब लोग केसों में फंसे हैं। उन्होंने उनको मरा हुआ भी दिखा दिया और दस्तखत भी दे दिये और दोनों ने मिलकर काफी तादाद में वह पैसा ले लिया। मेरा ख्याल यह है कि जैसा अभी हमारे साथी जान साहब ने कहा कि हमें कोई मैकेनिज्म जरूर इंवाल्व करना पड़ेगा ताकि पात्र व्यक्ति को पैसा वक्त से मिल जाए। तो इसके लिए एक थर्ड मंथली स्टेटमेंट अधिकारियों की तरफ से छपे कि फलां गांव में इतने मरने वालों को यह दिया है। इससे दूसरे लोगों की चेकिंग हो जाएगी। यह मामला तब खुला जब वह पंचायत सेक्रेटरी पकड़ा गया। उसने 15 आदमी जिंदा जो थे, उनके रिकार्ड में मारकर पैसा निकाल लिया। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि कोई ऐसा मेकेनिज्म इंवाल्व करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को इनमें इन्वाल्व किया जाए और उनके ऊपर चेक और काउंटर चेक हो। इसलिए इसको आप ऐसा बना दीजिए जिससे पात्र व्यक्ति को भी यह मदद मिले। सरकार को बेनीफिट देना चाहती वह सही शख्स को मिले यह बहुत जरूरी चीज है। वरना कहीं ऐसा न हो आप जिनकी मदद करना चाहते हैं उनको न मिलकर वह बरबादी की तरफ न चली जाए।

श्री नागेन्द्र ओझा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं कुछ मुद्दों पर क्लेरीफिकेशन चाहता हूं पहले तो मैं इसका स्वागत करता हूं जो यह राशि असिस्टेंस प्रोग्राम में बढ़ाई गई है। लेकिन इसके चलते आपकी नार्मल रिक्वायरमेंट क्या होगी? क्या जो नार्मल रिक्वायरमेंट है उसकी राशि विमुक्त की जा रही है? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि 1997-98 में टोटल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर नार्मल रिक्वायरमेंट 932 करोड़ रुपया थी और उसको घटाकर 599.65 कर दिया गया है। जो नार्मल रिक्वायरमेंट है, इस बढ़ोत्तरी के बाद वह क्या है और उसके अनुसार राशि विमुक्त की जा रही है या नहीं? दूसरा, ओल्ड एज पेंशन अभी तक ज्यादा लोगों को नहीं मिल रही है। इसकी प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए क्योंकि अभी भी जितने इस राशि के पाने के हकदार इस प्रोग्राम के अंदर हैं, जो बेनिफिशरीज हो सकते हैं, सभी कवर नहीं किए गए हैं। इस मामले में क्या कोई ढीली प्रक्रिया अपनाई जाने वाली है कि नहीं ताकि सभी लोगों को इसके अंतर्गत कवर किया जा सके?

SHRI BABAGOUNDA PATIL: Madam, about the release of funds to the KBK districts under NEPC, I need a separate notice. Then, about the target, it is 100%...

श्री खान गुफरान जाहिदी: इससे पहले कि आप जवाब दें मैं यह पूछना चाहता हूं कि बड़ी चीज आपने बढ़ाई है लेकिन 75 रुपये में आपने इजाफा क्यों नहीं किया है? यह तो बुनियादी चीज थी। 75 रुपये भी बढ़ने चाहिए थे। 5 हजार का आप 10 हजार रुपये मरने पर दे रहे हैं। तो इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं। खाने-पीने की जो चीजें हैं, जिनसे आदमी जिंदा रहता है। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75 रुपये को भी आप डबल करें। जब सब को डबल कर रहे हैं तो इसको क्यों नहीं कर रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): पहले उनको जवाब तो देने दीजिए।

SHRI BABAGOUNDA PATIL: I am happy that the hon. Members have given their suggestions. The suggestion about giving money through cheques, will be examined by the Ministry. An hon. Member suggested that instead of giving cash, it is better to give in the form of foodgrains. This will also be examined by the Ministry. When I visited some of the States, I had advised the Chief Secretaries to make some enquiry with food and nutrition research institutions and consider whether instead of giving cash to pregnant women, it is better to given them scientifically prepared nutritious food. Madam, the State Governments are implementing this scheme. We are releasing funds according to the demand of the State Governments. If the State Governments ask for more money, we are ready for that. An hon. Member has asked me to furnish the information about the list of beneficiaries. Regarding this, I have asked the State Government to publish a gazetteer furnishing the information regarding beneficiaries of all our programes.

And another hon. Member had suggested to raise the old-age pension which is now Rs. 75 (*interruption*)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Fernandes, the Minister is responding to your query.

SHRI BABAGOUNDA PATIL: We will examine the hon. Member's suggestion.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Thank you very much (*interruption*)

श्री सनातन बिसिः उपसभाध्यक्ष महोदया, उड़ीसा को जो 1997-98 में प्लान का जो रुपया दिया गया है,

MISS SAROJ KHAPARDE: He is asking for another notice. This is not Question Hour. He is giving a statement.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): That is why I was trying to attract your attention that the Minister is replying and you have to give a separate notice for this. You ask for a clarification on that. (*interruption*)

SHRI SANATAN BISI: You can give it to me.

SHRI BABAGOUNDA PATIL: I will give it after ascertaining the date of release.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE):Did you get the answer?

SHRI SANATAN BISI: Yes, Madam.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Mr. Bisi is always happy with the answer.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): But the Minister has not given any *pucca* assurance as such. Now, the House is adjourned till 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at fifty-six minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 4th August, 1998.